प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
30.10.2025 / प्रादेशिक समाचार / 15.00 बजे

भेंट

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शाम नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। उन्होंने प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अगले वित्त वर्ष के आबंटन में 2 सौ करोड़ रूपए की वृद्धि करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी आग्रह किया, ताकि 90–10 का अनुपात बना रहे। उन्होंने प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की भी जानकारी दी और कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए प्रयासरत्त है।

.....

धर्माणी

नगर व ग्राम नियोजन और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रूपए की लागत से एक भव्य खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा। ये परिसर स्थानीय युवाओं के लिए एक नई खेल पहचान स्थापित करेगा। घुमारवीं में आज खेल परिसर निर्माण स्थल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को न केवल शिक्षा बल्कि खेलों में भी नई ऊंचाईयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। धर्माणी ने कहा कि प्रदेश में जिला व उपमंडल स्तर पर खेल अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है।

.....

किन्नौर महोत्सव

राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव आज से रिकांगपिओ में शुरू हो रहा है। इस चार दिवसीय महोत्सव के दौरान देश–प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक दल अपनी संस्कृति के रंग बिखेरेंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ रिकांगपिओ से हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट––

डिस्पैच *– यह मेला सिर्फ एक वार्षिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास और व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। महोत्सव में 31 अक्टूबर को मैराथन दौड़ का भी आयोजन होगा। इसके अलावा 30 व 31 अक्टूबर को नेशनल ट्राइबल फेस्टीवल भी मनाया जा रहा है। इस वर्ष देश के 26 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आमंत्रित किया गया है। महोत्सव में जनजातीय शिल्प, कला और संस्कृति प्रदर्शनी, जनजातीय फिल्म प्रलेखन, साहित्य, वनों से प्राप्त उत्पाद, पारंपरिक खाद्य व्यंजन और जनजातीय चिकित्सा पद्धतियों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी। सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के लिए विभागीय प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।*

.....

सिंकदर कुमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को अपनी मंजूरी दे दी है और यह आयोग अगले 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने केन्द्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पैंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार जहां अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति गंभीरता से आगे बढ़ रही है, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर्मचारियों और पैंशनरों का शोषण करने में लगी हुई है।

जीएसटी–सुधार

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा 22 सितंबर को कई क्षेत्रों में वस्तु और सेवाकर– जीएसटी दरों में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई थी। आज, हम बात करेंगे कि कैसे परिधान और जूता क्षेत्र में नई जीएसटी दरों से नागरिकों को सहायता मिल रही है। एक रिपोर्ट––

डिस्पैच–

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने परिधान और फुटवियर क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान की है। इन सुधारों का उद्देश्य युवा निर्माताओं पर बोझ कम करना, उत्पादन को अधिक लागत प्रभावी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि गुणवत्तापूर्ण रेडीमेड कपड़े और फुटवियर उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो। नए का ढांचे के तहत रेडीमेड परिधानों पर दो हजार पांच सौ रूपये तक के लिए जीएसटी हटाकर 5: कर दिया गया है। इस सुधार ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू मांग को बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार मानव निर्मित धागों पर कर की दर 12: से घटकर 5: कर दी गई है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। इसके अलावा 2500 तक के फुटवियर पर 12: के बजाय केवल पांच प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। इसे स्टाइलिश फुटवियर युवा और मध्यम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं। इस जीएसटी सुधार ने देश के विनिर्माण आधार को महत्वपूर्ण रूप से प्रसारित किया है, उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया है और इन उत्पादों को अधिक किफायती बनाया है।

कार्यशाला

हिमाचल सहित उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के वैटलैंड संरक्षण के विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आज शिमला में शुरू हुई। इस कार्यशाला का आयोजन राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद और पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद के संयुक्त सदस्य सुरेश कुमार अत्री ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य वैटलैंड के संरक्षण, प्रबंधन और इनके विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए अनुभव साझा करना और नई रणनीति पर विचार–विमर्श करना है।